भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1621

जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 27 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

फेम योजना का चरण-II

1621. कुमारी शैलजा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फेम (एफ ए एम ई) योजना के चरण-I के तहत इसके उद्देश्य की पूर्ति करने में सक्षम रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस योजना के लिए स्वीकृत तथा आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 'फेम' योजना के चरण-II को शुरू करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी समय सीमा तथा विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ङ) 'फेम' योजना के तहत अब तक उपलब्ध कराई गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ङ) इस समय फेम योजना का चरण-I चल रहा है और यह दिनांक 31 मार्च, 2019 तक है, जिसे बल दिए जाने वाले चार क्षेत्रों नामतः मांग सृजन, प्रौद्योगिकी विकास, चार्जिंग अवसंरचना और प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। मांग सृजन के अंतर्गत इलैक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के व्यापक अंगीकरण हेतु खरीद मुल्य में कटौती के रूप में इलैक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के खरीदारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा योजना की अधिसूचना के अनुबंध 13 में दिया गया है जो विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है। आज की तारीख तक, योजना के तहत एक्सईवी के खरीदारों द्वारा मांग प्रोत्साहन के रूप में लगभग ₹300 करोड़ का दावा किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास, चार्जिंग अवसंरचना और प्रायोगिक परियोजना के तहत प्राप्त विशेष परियोजनाओं/प्रस्ताव का भी निधियन किया गया है। निधि के आवंटन और उपयोग का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

वर्ष	आबंटित निधि	उपयोग की गई निधि
2015-16	₹75 करोड़	₹75 करोड़
2016-17	₹144 करोड़	₹144 करोड़
2017-18	₹165 करोड़	₹165 करोड़
2018-19	₹195 करोड़	₹74 करोड़ (लगभग)

फेम योजना का चरण-I सफल रहा है और योजना से अधिगम को प्रस्तावित योजना द्वितीय चरण में शामिल किया गया है। फेम योजना के चरण-II में सार्वजनिक परिवहन में इलैक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को और बढावा देने का प्रस्ताव है तथा बाजार सृजन और मांग एकीकरण के द्वारा ईवी के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना है, मसौदा योजना में चार्जिंग अवसंरचना उपलब्ध कराने, ईवी प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान एवं विकास और स्वदेशीकरण को बढ़ाने सहित ईवी उद्योग की होलिस्टिक वृद्धि की परिकल्पना है। योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

*****